

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

बिलासपुर, शुक्रवार 3 जुलाई 2026

शासकीय विद्यालयों के गणवेश बदले, स्लेटी स्कर्ट/ पैट के साथ नीले रंग की चेक शर्ट

बदल दिए रंग, लेकिन बदहाली यथावत... नई यूनिफॉर्म का कपड़ा पतला, पहनने में संकोच कर रहीं बच्चियां

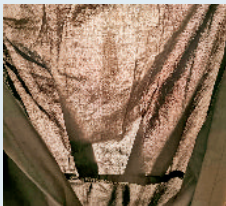
हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के साथ ही विद्यालयों में यूनिफॉर्म वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। स्कूलों में यूनिफॉर्म तो वितरित हो गए हैं, लेकिन विद्यार्थी विशेषकर छात्राएं इन्हें पहनने में संकोच कर रही हैं। इसका कारण गणवेश की

गुणवत्ता है। जो गणवेश स्कूलों में वितरित किए गए हैं, वे इतने पतले हैं कि इनसे आसानी से आर-पार देखा जा सकता है। लड़कों को इसे पहनने में अधिक दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन लड़कियां इसे पहनने में असहज महसूस कर रही हैं। प्रदेश के हथकरघा विपणन संघ द्वारा इसे तैयार किया गया है। ►►शेष पेज 6 पर



59 लाख सेट के लिए 156 करोड़ की राशि हुई थी स्वीकृत



सूचना दें, रिप्लेस करवाएंगे

जहां कहीं भी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें हैं वे हमें सूचित करें। हम तत्काल रूप से ऐसे गणवेश का रिप्लेस करवाएंगे।

—एमएम जोशी सचिव, हथकरघा संघ

रायपुर व दुर्ग में एक ही सेट

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में गणवेश के लिए शासन द्वारा 156 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। 59 लाख यूनिफॉर्म सेट इस राशि से तैयार किए गए हैं। प्रत्येक छात्र को दो-दो सेट प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सरगुजा, बिलासपुर व बस्तर शिक्षा संभाग में दो-दो सेट यूनिफॉर्म वितरित की जा चुकी है, जबकि रायपुर व दुर्ग में अधिकतर जगहों पर एक-एक सेट गणवेश का ही वितरण हो सका है। विभाग द्वारा यहां भी 15 जुलाई तक दो सेट वितरण का लक्ष्य पूर्ण करने की बात कही जा रही है।

स्कूलों में मंत्रींचार के आदेश को चुनौती, याचिका खारिज

बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में मंत्रींचार शुरू करने के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्ता बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब्दुल सलाम रिजवी की ओर से पेश याचिका में कहा गया था कि यह आदेश भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने 12 जून 2026 को जारी राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग याचिका में की थी।

याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि संविधान के अनुसार राज्य को धार्मिक तटस्थता बनाए रखने और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान प्रदर्शित करने का दायित्व है। स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश, विशिष्ट हिंदू धार्मिक प्रार्थनाओं और मंत्रों को अनिवार्य विद्यालयी गतिविधियों के रूप में निर्धारित करके, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य समुदायों के अंत्रों के साथ भेदभाव करता है और उनकी अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। याचिका पर जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में यह कहीं भी चालू नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फूट देते हुए कहा कि जब इस तरह की गतिविधियां हो तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका खारिज कर दी है।

बुआई में देरी से उत्पादन कम होने की आशंका, किसानों को अब बारिश का इंतजार

जून सूखा गया, अब बिना बारिश हर दिन किसानों को पड़ रहा भारी



राजनांदगांव- सधिन अगहरि, खैरागढ़- चैतन्य तिवारी, मोहला- एनिशपुरी गोस्वामी, कवर्धा-महेश मिश्रा, दुर्ग- देवीलाल साहू, जगदलपुर- महेंद्र विश्वकर्मा की विशेष रिपोर्ट

जून का महीना लगभग सूखा बीत गया। अब बिना बारिश के बीत रहा हर दिन किसानों के लिए भारी पड़ रहा है। किसानों की पूरी उम्मीद अब जुलाई पर टिकी है, उसमें भी पहला सप्ताह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानकार बताते हैं कि इस हफ्ते अगर बुआई के लायक बारिश होती है तो खेती सम्भल सकती है। वरना असंचित क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पर्याप्त नमी नहीं होने से अधिकांश खेत अभी भी खाली



दस फीसदी बुवाई

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी बारिश की कमी का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई गांवों में खेतों की जुताई पूरी हो चुकी है, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण धान की रोपाई शुरू नहीं हो सकी है। खैरागढ़ जिले में जून के दौरान सामान्य वर्षा की तुलना में लगभग आधी बारिश दर्ज की गई, जिससे अब तक केवल 10 से 12 प्रतिशत क्षेत्र में ही बुवाई हो सकी है।

सिंचाई सुविधा वाले किसान कर रहे बुवाई

दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में भी स्थिति लगभग समान है। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बादल आए लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। इससे कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे बोरेवेल और पंप के सहारे सीमित क्षेत्र में बुवाई कर रहे हैं। लेकिन वर्षा आधारित खेती करने वाले अधिकांश किसान पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं।

बुआई में देरी की हो सकती है भरपाई



मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में लगभग 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। कृषि विभाग के उप संचालक जे.एल. मंडवी के अनुसार किसानों ने खेती की तैयारी पूरी कर ली है तथा अतिरिक्त बीज का भंडारण भी किया गया है। विभाग को उम्मीद है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो बुवाई में आई देरी की भरपाई हो सकती है।



कवर्धा में 74 फीसदी बोआई

कबीरधाम जिले में मानसून सक्रिय होने के बाद खरीफ फसलों की बोनी का कार्य तेजी से जारी है। कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में कुल 1 लाख 92 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न खरीफ फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख फसल धान है, जिसके लिए 88 हजार 200 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। अब ►►शेष पेज 6 पर

हफ्ते भर की बारिश ने खेतों में लाई जान

बस्तर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में मानसून का देरी से आगमन और कम वर्षा के कारण धान की खेती का रकबा कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुआ है। बस्तर की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसून और धान की उपज पर निर्भर है। मानसून के कमजोर रहने और अनियमित बारिश की वजह से धान की रोपाई और बोनी में रिश्डने की समस्या कुछ क्षेत्रों में है वहीं हफ्ते भर की बारिश ने खेतों में जान ला दी है इसीलिए रूपा का काम तेजी से शुरू हो गया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ►►शेष पेज 6 पर

खबर संक्षेप

एससीएलएससी की अध्यक्ष होंगी न्यायमूर्ति नागरत्ना

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने 29 जून से प्रभावी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना को

नामित किया है। सीजेआई ने 29 जून, 2026 से प्रभावी भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

तीन राज्यों की तीन विस सीटों पर 30 को उपचुनाव

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने बुधस्पतिवार को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। इन सीटों के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना तीन अगस्त को होगी। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन के विधायक पद से इस्तीफा देने से बांकीपुर, कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में दोषी के बाद सीट खाली है।

दो सगे भाइयों समेत तीन मजदूरों की मौत

गोंडा। यूपी के गोंडा जिले में बृहस्पतिवार सुबह सरिया लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दो सगे भाइयों समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान

तरबर्गज थाणा क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी रवींद्र पासवान (40), उसके भाई राजेंद्र पासवान (45) और राम गुलाम पासवान (55) के रूप में हुई है।

आकाशीय बिजली से तीन की गई जान

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। पहली घटना बुधवार को गड़वार थाणा क्षेत्र के धर्मनपुर गांव में हुई, जहां मुख्तार राम (55) और उसका भाई अवधेश (45) खेत में काम कर रहे थे। पुआकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें रतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया।

चार्ल्स शोभराज के चेले जॉन ने देशभर के 300 लग्जरी होटलों में ली मुफ्त में सेवाएं, रायपुर में धरा गया



गिरफ्तार जालसाज 15 साल देश के अलग-अलग राज्यों की जेल में रहा, बाकी समय होटलों में बिताया

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

रायपुर के होटल हयात में मुफ्त सेवाएं लेते पकड़े गए ठगराज की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। उसने देशभर के तकरिबन 300 होटलों में ठगी-चोरी की और लग्जरी लाइफ जीता रहा। इस ठग का नाम बिंगसन जॉन है। 69 वर्षीय जान को तेलीबांधा इलाके के फाइव स्टार होटल हयात में एंटी क्राइम एंड सायबर यूनिट ने दबोचा है। पूछताछ में पता चला कि जान ठगराज चार्ल्स शोभराज को अपना आईडियल मानता है। जान ने होटल हयात में ►►शेष पेज 6 पर

जेल को मानता है होम स्टे

गिरफ्तार जालसाज ने 1990 में ठगी करने शुरू किया था। 21 वर्षीया मंगेश्वर की मौत के बाद उसने शादी करने का विचार त्याग दिया और ठगी करने लगा। सबसे पहले वो 1996 में ठगी करने पर गिरफ्तार हुआ। अब तक उसने अपने जीवन काल के कुल उम्र में से 15 वर्ष जेल में व्यतीत की है। पकड़े जाने पर वह पुलिस को गुमराह करने की बजाय अपना अपराध कबूल कर लेता है। जालसाज जेल को होम स्टे तथा होटलों को पर्यटन स्थल मानता है। पूछताछ में पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बिंगसन पहले गाइड का काम करता था।

फिल्मी अंदाज में जीता था जिंदगी

पूछताछ में जालसाज ने पुलिस को बताया कि पिछले 36 वर्षों से उसकी जिंदगी जेल और महंगे होटलों के बीच ही गुजर रही है। जेल से बाहर निकलते ही वह किसी नए शहर के पांच सितारा होटल को अपना निशाना बनाता था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ देशभर में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है।

बारिश से बचने खड़े थे पेड़ के नीचे, गाज से मां-बेटी की मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के ग्राम पतरापारा में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मां-बेटी खेत में काम करने गई थी तभी दोपहर के अचानक तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों पेड़ के नीचे खड़ी थीं, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं। एक साथ एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो जाने से गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम पतरापारा निवासी मानती टेकाम (33 वर्ष) गुरुवार को खेत में काम करने 14 वर्षीय पुत्री कुमार विमला टेकाम के साथ गई थी। दोपहर में दोनों खेत में काम कर रही थी तभी अचानक तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने मां-बेटी खेत के समीप स्थित एक सेमल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई, जिसकी ►►शेष पेज 6 पर

कांग्रेस सरकार में ही बनी विधायक कालोनी की योजना उसके बाद दो साल में 15 हेक्टेयर भूमि पर हो गया कब्जा

सोशल मीडिया में तैर रही सूची कई के कब्जे में विशाल भूखंड

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

नवा रायपुर इलाके के ग्राम नकटी में गरीबों के मकान तोड़ने के मामले को लेकर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने वहां बनने वाली विधायक कालोनी में मकान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस योजना की नींव ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। मकान तोड़ने के मामले में अब ये तथ्य सामने आया है कि वहां वर्ष 2021 में केवल 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कच्चे मकान एवं बाड़ी-खहिरान पाए गए थे, लेकिन वर्ष 2023 में यानी दो साल बाद वहां की ►►शेष पेज 6 पर



44 परिवारों के पास इसी गांव में पहले से हैं मकान केवल 16 परिवार ऐसे जिनके पास मकान नहीं

तीन साल में हुआ ये घटनाक्रम

नकटी मामले में वर्ष 2020 से लेकर 2023 यानी तीन साल के दौरान क्या घटनाक्रम रहा, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले 2020 में हाउसिंग बोर्ड ने कलेक्टर रायपुर को नकटी में 15.47 हेक्टेयर भूमि को सामान्य आवासीय योजना के लिए आवंटन की मांग प्रस्तुत की थी। यानी प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय इस योजना की नींव रखी गई थी। इसके बाद भू-अभिलेख की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और फिर नायब तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में आपति आमंत्रित कर सार्वजनिक इशतहार जारी किया गया। ►►शेष पेज 6 पर

सीएम को पत्र



कांग्रेस के धमतीर विधायक ओंकार साहू और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने नकटी में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी नकटी से अन्यत्र स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि नकटी गांव में पिछले 30-40 साल से रह रहे ►►शेष पेज 6 पर

अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, एलजी ने दिखाई हरी झंडी

बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ रवाना हुए भक्त

4,822 श्रद्धालु 259 वाहन 670 कंपनियां तैनात एजेंसी ►► जम्मू

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। कुल 4,822 श्रद्धालु 259 वाहनों में सवार होकर अमरनाथ गुफा की ओर निकले। ये श्रद्धालु दो मार्गों - पहलगांव और बालटाल के रास्ते यात्रा करेंगे। मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी



श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचकर यात्रियों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखाया। इस बार यात्रा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगांव और बालटाल, दोनों ►►शेष पेज 6 पर

57 दिन चलेगी यात्रा

बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 57 दिव तक चलेगी। यह 3 जुलाई से पहलगांव और बालटाल, दोनों रास्तों से शुरू होगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। इस मौके पर डीजीपी नलिन प्रभात, ररेशल डीजीपी एस जे एम गिलान, जम्मू डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, आईजीपी जम्मू मीम सेन तुंगी, आईजीपी सीआरपीएफ अमील होमकर, आईजीपी ट्रैफिक एम सुलेमान चौधरी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू डॉ राकेश मिहतास मौजूद रहे।

दो मार्ग से यात्रा

श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल और पहलगांव बेस कैंप की ओर बढ़ा, जहां से तीर्थयात्री शुक्रवार सुबह 3,880 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। श्रद्धालु अमरनाथ में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे गुनवान-पहलगांव रास्ते या गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे छोटे बालटाल मार्ग से यात्रा कर सकते हैं।

राम मंदिर में लोगों की समुद्धि के लिए प्रार्थना

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को यहां स्थित राम मंदिर में दर्शन किए और लोगों की सुखहाली, कल्याण तथा समुद्धि के लिए प्रार्थना की। जम्मू में स्थित यह संदियों पुराना मंदिर उन साधु-संतों के लिए आश्रय स्थल है, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। पुरानी मंडी क्षेत्र स्थित मंदिर में 400 से अधिक साधु और साधवियां पहुंच चुके हैं, जो दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यहां एकत्र हुए हैं।

कोतवाली एसीपी के नेतृत्व में पांच सदस्यी टीम गठित

ड्रग क्वीन नव्या मलिक केस की जांच के लिए एसआईटी गठित

हरिभूमि न्यूज़-रायपुर

चर्चित नव्या मलिक ड्रग केस की कोर्ट से अनुमति लेने के बाद नए सिरे से जांच शुरू की गई है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर पांच सदस्यी जांच टीम गठित की गई है। जांच के लिए कोतवाली एसीपी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच सदस्यी टीम गठित की गई है। टीम में दो टीआई के साथ दो अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है।

पुलिस कमिश्नर के अनुसार नव्या मलिक तथा उनसे जुड़े लोगों के जब्त मोबाइल के सीडीआर निकालकर नए सिरे से जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन सभी के बैंक ट्रांजेक्शन तथा ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य सिंडीकेट के साथ संबंध की जांच की जा रही है। नव्या मलिक तथा उनसे जुड़े लोगों के फॉरिन ट्रिप की जांच करने ईडी ने अलग से केस से संबंधित दस्तावेज देने पुलिस से मांग



की थी। ड्रग्स रैकेट के खिलाफ अभियान में पकड़ी गई नव्या मलिक और विधि अग्रवाल रायपुर समेत कई राज्यों में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चलाती थीं। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाकर रईसजादों को सप्लाई की जाती थी। नव्या पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। इन दोनों को पुलिस ने हथ आहूजा, मोनू विश्नोई और दीप धनोरिया की 23 अगस्त 2025 को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर

गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में तब खुलासा हुआ कि ड्रग्स तस्करी के हाई-प्रोफाइल केस में नव्या कई हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में थी। पुलिस की जांच में पता चला कि नव्या और विधि करीब 850 रईसजादों के संपर्क में थी और उनके लिए ड्रग्स सप्लाई होती थी। बताया जा रहा है कि 850 लोगों में से कोई हॉटेल कारोबारी तो कोई बड़े राजनेता का बेटा है।

एसआईटी इन प्रमुख बिंदुओं पर करेगी जांच

- एमडीएमए का मूल स्रोत- ड्रग कहां से लाया गया और इसका मुख्य सप्लायर कौन था।

- पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच- रायपुर, मुंबई और अन्य राज्यों से जुड़े सप्लायर, कुरियर और रिसीवर की पहचान।

- नव्या मलिक और अन्य आरोपियों की भूमिका- ड्रग की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण में किसकी क्या भूमिका थी।

उड़ीसा से मुंबई ले जा रहा था 8.78 लाख का गांजा, रेलवे स्टेशन पर यूपी का अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूतः रायपुर

रेलवे सुरक्षा बल और आबकारी विभाग ने रेलवे स्टेशन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। टीम ने स्टेशन के सर्कुलेंटिंग एरिया से एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 8.78 लाख रुपये कीमत का 17.5 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशों में 1 जुलाई को स्टेशन परिसर में विशेष जांच और निगरानी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान स्टेशन के सर्कुलेंटिंग एरिया स्थित सार्वजनिक शौचालय के पीछे से टीम ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। आरपीएफ पोस्ट रायपुर के प्रभारी निरीक्षक कर्मपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि जब टीम ने उसके पास मौजूद एक ट्रॉली बैग और एक पिट्टू बैग की तलाशी ली, तो उसमें 14 बंडलों में भरा हुआ कुल 17.570 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 8,78,500 रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज

- मनी ट्रेल की पड़ताल- बैंक खाते, यूपीआई, नकद लेन-देन और ड्रग कारोबार से हुई कमाई की जांच।

- डिजिटल फॉरेंसिक जांच में मोबाइल फोन, लैपटॉप, काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर), वाट्सएप चैट, इंटरनेट मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण।

- हाईप्रोफाइल पार्टियों का कनेक्शन निजी पार्टियों, क्लबों, पब और कथित टेक्नो पार्टियों में ड्रग की सप्लाई की जांच।

- ड्रग खरीदने वालों की पहचान चार्जशीट में दर्ज नामों सहित अन्य उपभोक्ताओं और नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच।

- पुराने मामलों और अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच, क्या इस गिरोह के तार अन्य राज्यों या पुराने एनडीपीएस मामलों से जुड़े हैं।

- संरक्षण और मिलीभगत क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति, कारोबारी या अन्य लोगों ने नेटवर्क को संरक्षण या आर्थिक सहायता दी।

बिजली बिल का विलंब से भुगतान करने पर अब प्रति दिन के हिसाब से लगेगा सरचार्ज

चार हजार के बिल पर एक दिन के लगेगे 1.60 रुपए, पहले पूरे माह के 60 रुपए लग जाते थे

हरिभूमि न्यूज़ »» रायपुर

प्रदेशभर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अब जुलाई के बिजली बिल का विलंब से भुगतान करने पर पूरे माह के स्थान पर प्रतिदिन के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। पहले एक दिन का विलंब होने पर भी पूरे माह का सरचार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। इसी के साथ अब एडवांस में बिल जमा करने वालों की थोड़ा सा झटका लगेगा। पहले इसमें 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, इसको अब 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। आमतौर पर कोई उपभोक्ता एडवांस में पैसा जमा नहीं करता। पुराने नियमों के मुताबिक यदि कोई उपभोक्ता बिल भुगतान की अंतिम तिथि के बाद महज एक या दो दिन की देरी से भी बिजली बिल का भुगतान करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूल लिया जाता था। ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता का बिल चार हजार रहता है तो उससे पूरे माह का 60 रुपए लिया जाता है। अब नए नियम के बाद अब विलंब शुल्क की गणना अब प्रतिदिन के हिसाब से होगा। उपभोक्ता का जितने का बिल होगा, उस बिल के हिसाब से अब विलंब अधिभार 0.04



प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जितने दिन बिल जमा करने में देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का शुल्क देना होगा। एक दिन की देरी पर मामूली शुल्क लगेगा। यदि चार हजार का बिल है तो एक दिन का 1.60 रुपए ही देने पड़ेंगे। इस हिसाब से जितने दिन विलंब होगा, उतने दिनों का पैसा लगेगा। पहले एक साथ एक माह का शुल्क लिया जाता था। अब एक माह का विलंब होने पर 1.2 प्रतिशत के हिसाब से चार हजार पर 48 रुपए ही लगेगे।

ज्यादा बिल पर मिलेगी बड़ी राहत

नए नियम से उनको ज्यादा फायदा होगा जिनके बिल ज्यादा आते हैं। किसी उपभोक्ता का अगर पचास हजार बिल है तो उनको पहले एक दिन का विलंब होने पर 750 रुपए लग जाते थे लेकिन अब एक दिन के महज 20 रुपए लगेंगे। इसी तरह से जिनका बिल लाखों में रहता है, उनको बड़ी राहत मिलेगी।

पीडीएस संघ की कई मांगों पूरी, हड़ताल वापस ली

हरिभूमि न्यूज़ »» रायपुर

उचित मूल्य की दुकानों के संचालक 5 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले थे, जिसे अब स्थगित कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों और विभाग के अधिकारियों के बीच दो दिन से चल बातचीत के बाद संघ की कई

■ पीडीएस संघ एवं विभागीय अधिकारियों के बीच बैठक रही सफल

मांगों को पूरा कर दिया गया है। इसमें बारदाना से ले क र एनएफएसए एवं नमक का आश्वासन मिला है। जिसका भुगतान पिछले कई साल पूरा करने का आश्वासन मिला है। नमक पूरक पोषण 5 साल से, बारदाना का एक साल से अटका था कमीशन- पीडीएस संघ के अध्यक्ष ने बताया कि बारदाना का कमीशन पिछले एक साल से अटका हुआ था, वहीं नमक पूरक पोषण का कमीशन वर्ष 2021 से नहीं मिला है। इसी प्रकार एनएफएसए चावल का कमीशन भी पिछले कुछ महीनों से अटका था। कमीशन नहीं मिलने के कारण दुकानदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि पिछले कई साल से अपनी मांगों को लेकर कई साल से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी। इसे देखते हुए आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए 5 जुलाई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। हालांकि विभाग इस बार उनकी मांगों को लेकर न केवल गंभीरता दिखाई, बल्कि कई मांगों को पूरा भी किया है। उन्होंने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उनके द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसमें से लगभग आधी मांगों को पूरा कर दिया है। कमीशन की राशि जारी, एक सप्ताह में दुकानदारों के खाते में आएगी- उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम सिद्दिकी, उप सचिव विभोर अग्रवाल, अपर संचालक नीलम एल्मा की उपस्थिति में नया रायपुर में संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि रुकी हुई कमीशन की राशि को जारी कर दिया है, साथ ही सप्ताहभर के अंदर सभी दुकानदारों को यह राशि ट्रांसफर हो जाएगी।

केंद्रीय योजनाओं की राशि वेंडरों को देने के बजाय सरकारी खातों में पड़ी रही, समीक्षा से खुलासा

खातों में पैसा, काम और भुगतान दोनों प्रभावित, समीक्षा में उजागर हुई वित्तीय अनियमितता

हरिभूमि न्यूज़ः रायपुर

छत्तीसगढ़ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वित्तीय प्रबंधन की एक बड़ी खामी सामने आई है। विभागों की समीक्षा में पाया गया है कि योजनाओं के तहत जारी की गई राशि का बड़ा हिस्सा समय पर वेंडर्स और सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के बजाय विभिन्न शासकीय एजेंसियों और विभागों के खातों में पड़ा हुआ है। इसके बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और एसएनए स्पर्श व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई विभागों में राशि अंतिम भुगतान तक नहीं पहुंच रही है। जबकि केंद्र सरकार को जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली का उद्देश्य यही है कि धन केवल वास्तविक भुगतान की आवश्यकता होने पर ही जारी हो और सीधे अंतिम लाभार्थी या वेंडर तक पहुंचे।

वित्त विभाग का मानना ​​है कि जब राशि लंबे समय तक विभागों या क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों में पड़ी रहती है तो न केवल सरकारी धन का प्रभावी उपयोग प्रभावित होता है, बल्कि विकास कार्यों की गति और ठेकेदारों तथा सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान भी प्रभावित होता है।इसी कारण

राशिफल

	आशा-निराशा के भग भवन में हो सकते हैं। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें।
मेघ	
	धैर्यशीलता बनाये रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव की सम्भावना बन रही है। परिश्रम अधिक रहेगा।
वृष	
	मन प्रसन्न रहेगा। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। विवाद की स्थितियां बन सकती हैं।
मिथुन	
	आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परन्तु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। धर्म के प्रति श्रद्धावान रहेंगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे।
कर्क	
	नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी, परन्तु किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं खत्म होगी।
सिंह	
	शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। शैक्षिक कार्यों के लिए भी विदेश जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं।
कन्या	
	जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का सानिध्य मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
तुला	
	मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा, परन्तु पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। खर्च बढ़ेंगे।
वृश्चिक	
	मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु आत्मसंयत भी रहे। कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंताओं पर नियंत्रण बनाकर रखें।
धनु	
	शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आय में वृद्धि भी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें।
मकर	
	भागदौड़ अधिक रहेगी। परन्तु किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता के भी योग हैं।
कुंभ	
	मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। भाग-दौड़ भी अधिक रहेगी।

यूएसटीआर के एआई आधारित एलिफेंट एप को मिली वैश्विक पहचान

हरिभूमि न्यूज़ःरायपुर

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में एआई एलीफेंट अलर्ट ऐप तथा थर्मल ड्रोन आधारित हाथी निगरानी प्रणाली को विश्व की प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी पत्रिका एमआईटी टेक्नोलॉजी रीव्यू अमेरिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस लेख में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एआई आधारित थर्मल इमेजिंग तथा रियल-टाइम सामुदायिक चेतावनी प्रणाली के अभिनव उपयोग की सराहना की गई है।

लेख में उल्लेख किया गया है कि यूएसटीआर के घने जंगल में, जहां रात्रि के समय या कठिन भू-भाग में हाथियों की निगरानी चुनौतीपूर्ण होती है, वहां इन्फ्रारेड (थर्मल) सेंसर से युक्त ड्रोन का उपयोग किया जाता है। ये ड्रोन हाथियों की गतिविधियों का पता लगाते हैं, जिसके बाद



प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर एआई एलीफेंट अलर्ट ऐप के माध्यम से वन अमले एवं आसपास के ग्रामीणों को एसएमएस, फोन कॉल एवं व्हाट्सएप द्वारा 5 से 10

किलोमीटर के दायरे में तत्काल चेतावनी संदेश भेजते हैं। इससे मानव-हाथी संघर्ष की घटना को रोकने तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

एमआईटी टेक्नोलॉजी रीव्यू की स्थापना अमेरिका में वर्ष 1899 में मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा की गई है। यह विश्व की सबसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी पत्रिकाओं में से एक है, जो एआई, जलवायु प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा तथा उभरती वैज्ञानिक तकनीकों पर उच्च गुणवत्ता वाली शोधपरक एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। विश्वभर में नवाचारों और तकनीकी उपलब्धियों को पहचान दिलाने में इस पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की इस अभिनव पहल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान छत्तीसगढ़ की तकनीक-

संचालित वन्यजीव संरक्षण रणनीति को सफलता का प्रतीक है। इससे भविष्य में भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व तथा स्थानीय समुदायों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय

एमआईटी टेक्नोलॉजी रीव्यू में प्रकाशित होना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण तथा मानव सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रयास वैश्विक स्तर पर भी एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।

- **वरुण जैन**, डिप्टी डायरेक्टर, यूएसटीआर

शब्द पहेली - 6275												
1	2	3	4	5								
6		7		8							9	
10	11		12		13						14	
15											16	
17				18				19				
21											23	
24											25	
26						27	28		29	30		31
								32		33		
34												

बाएँ से दाए-

1. एक असुर जिसे शिव ने

वरदान दिया था -4

4. दान देने वाला -4

7. सवारी गाड़ी-2

8. संख्या, रत्न-2

10. जाप, मंत्र पाठ-2

12. आक्रमणकारी-5

14. अपशिष्ट पदार्थ-2

15. दिन, प्रहार-2

16. शीगा हुआ-2

17. शिशु पैदा हुआ

बच्चा-4

19. कीमती-4

20. आलसी, निष्ठाहीन-5

21. जिसे दीक्षा नहीं दी

गई हो-5

22. गारंटी, मुचलका-4

24. रस्तेदार-2

25. शेर, नाहर-2

26. पिटाई, चोट-2

27. निम्नता, न्यूनता-5

31. परिणाम, निष्कर्ष-2

32. महेंद्रसिंह धोनी को इस

नाम से भी जानते हैं- 2

33. मूल, कंद-2

34. उदाहरणार्थ-4

35. पितृवृक्ष-4

ऊपर से नीचे

2. सवरा, भोर-3

3. सांभर जैसा आहार -3

4. दैत्य, असुर-3

5. शहर-3

6. तरुण, जवान-4

9. एक महीन व

कीमती कपड़ा-4

11. ईश्वर, रव-7

13. डांट, फटकार,

भर्त्सना -3,4

14. भारत के पुर्व

प्रधानमंत्री-5,2

18. अधीन-3

19. निवेदन, प्रार्थना-3

21. असमतल-4

23. धमाका,

सनधनी-4

27. करिश्मा-3

28. बारीक-3

29. कपड़े धोनेवाला-3

30. पिटाई करना,

भांपना-3

शब्द पहेली - 6274 का हल

श	व	द	न	ज	अ	य	स	ब
ह	क	ख	ग	घ	ङ	च	ज	झ
ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प
फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	श
स	ख	ग	घ	ङ	च	ज	झ	ड
ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष
क	ख	ग	घ	ङ	च	ज	झ	ड
ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष
क	ख	ग	घ	ङ	च	ज	झ	ड
ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म	य	र	ल	व	श	ष
क	ख	ग	घ	ङ	च	ज	झ	ड
ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	फ
ब	भ	म						

कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन संघालित नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डिटिल अनुमान और योजनाओं में (पीएल) निकसी तथा ऐशन निर्धारण जैसे दावों के समक्षबद्ध निपटार पर विशेष जोर रहेगा। श्रम पर कर्मचारी मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के महत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026, कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 और कर्मचारी जमा-संचयन बीमा योजना, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने नई योजनाओं में ईपीएफओ अधिकाधिक्रियों द्वारा भविष्य निधि निकसी, ऐशन तथा समुह बीमा संबंधी दावों को 20 दिव के भीतर निपटार करने पर 12 प्रतिलि को दर से वार्षिक हंडारसक धाज को सख्त प्राथम्य दिया है।

चिंतन

बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे भारत-जापान संबंध

इंडो-पैसिफिक में अमेरिका की घटती रुचि और एक तरह से चीन को क्षेत्र की महाशक्ति के रूप में स्वीकार करने के बाद भारत और जापान के लिए जरूरी हो गया है कि वे इस क्षेत्र में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची को संयुक्त आर्थिक मंच में मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कि दोनों देश केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान नहीं खोज रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और तकनीक-संचालित एशिया की नींव रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भारत-जापान संबंधों का अमला चरण केवल सरकारी समझौतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दोनों देशों को निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच भी गहरे सहयोग को बढ़ावा देना होगा। जापान रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, प्रिंसिजन मैनुफैक्चरिंग और हरित प्रौद्योगिकी में विश्व अग्रणी है, जबकि भारत डिजिटल नैनोचिप, सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से उभरती शक्ति है। यदि इन दोनों की क्षमताओं का समन्वय होता है तो यह केवल दोनों अर्थव्यवस्थाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर निर्माण, क्लृप्त खनिजों (रेयर अर्थ) की आपूर्ति, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, हरित हाइड्रोजन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा तय करेगा। भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और कुशल मानव संसाधन के कारण नेक्स्ट मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जा रहा है, जबकि जापान की तकनीकी विश्वसनीयता इस परिवर्तन को गति दे सकती है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक कंपनियों के लिए चीन के विकल्प के रूप में एक मजबूत और विश्वसनीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर सकती है। साथ ही, दोनों देशों को लोगों के बीच संपर्क को भी प्राथमिकता देनी होगी। भारतीय छात्रों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए जापान में अवसर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर जापानी कंपनियों को भारत के युवा और कुशल कार्यबल से लाभ मिल सकता है। आज दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां मित्रता का मूल्य केवल कूटनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि साझा निवेश, साझा तकनीक और साझा भविष्य से तय होगा। भारत और जापान इसी दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यदि यह सहयोग योजनाओं से निकलकर समयबद्ध क्रियान्वयन तक पहुंचता है, तो आने वाले दशक में भारत-जापान संबंध केवल द्विपक्षीय सफलता की कहानी नहीं होंगे, बल्कि वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली स्तंभों में शामिल होंगे। यह साझेदारी वास्तव में विश्वास से विकास और साझेदारी से समृद्धि का ऐसा मॉडल बन सकती है, जिसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अस्थिर रव्ये ने दुनियाभर में उसकी स्थिति को कमजोर किया है। ईरान युद्ध के बाद खाड़ी देश अपनी सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के रिश्ते एक नए मोड़ पर खड़े हैं। इससे नई साझेदारियां बनेंगी और पुरानी साझेदारियां नया रूप लेंगी। ऐसे में भारत-जापान संबंध भी ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में यह दुनिया में नए बदलाव का जरिया भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और सबको एक-दूसरे की जरूरत है। मिलकर चलना ही सबसे हित में है।



क्या कागजों पर सिमट रही हैं ग्राम सभाएं

भारत की आत्मा गांवों में बसती है और उन गांवों की लोकतांत्रिक आत्मा 'ग्राम सभा' में निहित है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो नींव रखी थी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष इकाई ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा केवल स्थानीय शासन की एक संस्था नहीं है, बल्कि यह देश के हर ग्रामीण नागरिक को सीधे नीति-निर्माण, बजट निर्धारण और विकास कार्यों की निगरानी का अधिकार देने वाला एक सशक्त मंच है। परंतु समय के साथ इस बुनियादी लोकतांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली में कई विसंगतियां और चुनौतियां सामने आई हैं। इनमें सबसे बड़ी और चिंतनाजनक चुनौती यही है कि आज के इस तकनीकी युग के बावजूद ग्राम सभा की बैठकों में आम नागरिकों की भागीदारी घट रही है। मसलन, केंद्र सरकार और नीति आयोग की जारी ताजा रिपोर्ट ने जमीनी लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि यह अध्ययन भारत की ग्रामीण विकास नीतियों को 'संख्या-केंद्रित' से 'परिणाम-केंद्रित' बनाने का एक बेहद सटीक मार्गदर्शक दस्तावेज साबित हो सकता है। दरअसल, देश में जमीनी लोकतंत्र की इसी गंभीर समस्या का बारीकी से अध्ययन करें और इसका समाधान खोजने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में एक व्यापक राष्ट्रीय अध्ययन कराया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा तैयार की गई यह द्वि-खंडीय रिपोर्ट देश में नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और साक्ष्य-आधारित दस्तावेज है। जैसा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नागरिक-केंद्रित शासन देने के लिए जीवंत ग्राम सभाएं अनिवार्य हैं। जब तक देश के गांवों का अंतिम व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक शामिल होकर अपने गांव के भविष्य का फैसला करने में सक्षम और उत्सुक नहीं होगा, तब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना अधूरा रहेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट को 30 जून 2026 को नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज द्वारा इस जारी किया, जिसमें जमीनी लोकतंत्र की कमजोर होती नींव और उसकी चुनौतियों को लेकर चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। भागीदारी में सबसे बड़ी बाधाएं ग्राम सभाओं में लोगों का न आना केवल उदासीनता नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक और व्यावहारिक कारण हैं। इसमें आजीविका और समय के संकट के कारण 55.5 प्रतिशत भागीदारी न होने का सबसे बड़ा कारण है, इसमें ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा दैनिक मजदूरी या कृषि पर निर्भर है। जबकि व्यस्त कार्य दिनचर्या (41.74 प्रतिशत) और कृषि कार्यों की व्यस्तता (30.26 प्रतिशत) के कारण लोग अपनी दिहाड़ी छोड़कर बैठकों में नहीं आ पाते। इसके अलावा कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को लेकर खुलासा हुआ है कि प्रवासी परिवार (17.61 प्रतिशत), युवा (16.73 प्रतिशत), बुजुर्ग (15.80 प्रतिशत) और महिलाएं (13.40 प्रतिशत) ग्राम सभा की प्रक्रियाओं में सबसे कम शामिल हो पाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज का कथन है कि ग्रामीण भारत में आए बदलावों को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में गांवों तक बुनियादी सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हुई है। अब बारी जमीनी लोकतंत्र को और गहरा करने की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह अध्ययन महिलाओं, युवाओं और हरिणए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठाने में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्रालय जल्द ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर इस रिपोर्ट की सिफारिशों को जमीन पर लागू करेगा, ताकि देश की ग्राम सभाएं अधिक समावेशी और परिणामोन्मुख बन सकें। इस अध्ययन रिपोर्ट से एक बड़ा संदेश यह भी मिलता है कि ग्राम सभाओं को सफल बनाने का पैमाना केवल 'बैठक में भागीदारी' या 'हाजिरी रजिस्टर' नहीं होना चाहिए। वास्तविक सफलता इस बात में है कि चर्चाएं कितनी प्रासंगिक हैं, निर्णय कितने पारदर्शी हैं और शिकायतों का निवारण कितनी तेजी से होता है। जब तक ग्रामीण नागरिकों को ग्राम सभा के निर्णयों का जमीन पर वास्तविक असर नहीं दिखेगा, तब तक उनका भरोसा जीतना नामुमकिन है। ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों (विशेषकर महिला सपरंचों और वार्ड सदस्यों) के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वे ग्राम सभा की प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकें

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)



भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की सामान्य बनाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। दोनों देशों की 117 प्रमुख हस्तियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजे गए खुले पत्र ने इस बहस को नया आयाम दिया है। पत्र में संवाद बहाल करने, व्यापार शुरू करने, वीजा व्यवस्था आसान बनाने, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस को फिर चलाने, क्रिकेट श्रृंखला शुरू करने तथा दोनों देशों के बीच जमे अविश्वास को समाप्त करने की अपील की गई है। पहली नजर में यह पहल शांति और सद्भाव की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास प्रतीत होती है, लेकिन जब भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास, पाकिस्तान के व्यवहार और वर्तमान वैश्विक राजनीति को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव का विश्लेषण किया जाता है, तब कई गंभीर प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों की नीति अपनाई है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अनेक अवसरों पर पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। चाहे 1972 का शिमला समझौता हो, 1999 की लाहौर बस यात्रा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2015 में अचानक लाहौर जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलना, भारत ने हर बार यह संदेश दिया कि विवादों का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद से होना चाहिए। दुर्भाग्य यह रहा कि हर बार पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद ने इन प्रयासों को कमजोर किया। पाक का इतिहास यह बताता है कि उसने मित्रता के हर प्रयास के समानांतर आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का साधन बनाए रखा। 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर संसद पर हमला, मुंबई का 26/11 हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों तक पाकिस्तान की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में रही है। भारत ने कई बार ठोस सबूत भी प्रस्तुत किए, लेकिन पाकिस्तान ने या तो उन्हें नकार दिया या फिर आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने से बचता रहा। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि भारत किसी भी नए संवाद प्रस्ताव को केवल भावनात्मक आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और उर्जा संकट ने वहां की अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। हाल के वर्षों में जल संकट भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान के लिए भारत के साथ व्यापार और संबंधों की बहाली

जीवन का प्रथम अनुबंध किसको माना है?

अनुबंध चतुष्टय में 'अधिकारी' को प्रथम अनुबंध स्वीकार किया गया है। मानव की आध्यात्मिक और लौकिक यात्रा के निर्विघ्न संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक में इसके लिए योग्यता या पात्रता पद का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है, किसी कार्य के निष्पादनार्थ पात्रता प्राप्त करना।सामान्यतः प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र नहीं होता। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सफल और लोकमंगलकारी हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु अधिकारी (पात्र) व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सफल भी होता है और लोकमंगलकारी भी। इसलिए अधिकारी आत्मिक और जागतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव जीवन का प्रथम अनुबंध है। इसीलिए इसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। वेदांत में अधिकारी को परिभाषित करते हुए कहा गया-जिसने विधिवत ज्ञान प्राप्त कर काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है। नित्य, नैमित्तिक और उपासनादि कर्म करने से जिसकी बुद्धि परिकृत और अंतःकरण निर्मल हो चुका है, ऐसा पापरहित व्यक्ति ही विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी है। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने अधिकारी समझकर ही राम को विविध आयुध प्रदान किए, जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके। जैसे अधिकारी व्यक्ति का ज्ञान लोकमंगल के लिए होता है, उसी प्रकार अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियां समाज, देश और मानवता की रक्षा के लिए होती हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी अनधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका दुरुपयोग ही हुआ है।

अंतर्मन

आज की पाती

खतरनाक गर्मी का बढ़ता संकट

दुनिया के शहरों पर एक ऐसा संकट तेजी से गहराता जा रहा है, जो दिखाई कम देता है, लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है-खतरनाक गर्मी। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक शहरी इलाकों में अत्यधिक गर्मी से प्रभावित गरीबों की संख्या में लगभग 700 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले शहरी भविष्य की भयावह तस्वीर है, खासकर ग्लोबल साउथ, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए। गर्मी का यह संकट सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज और अनियोजित शहरीकरण से जुड़ा है। शहरों में कंक्रीट, डामर और धातु की अधिकता प्राकृतिक हरियाली को खत्म कर देती है। इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

- सुभाष साहू, बलौदाबाजार

करंट अफेयर

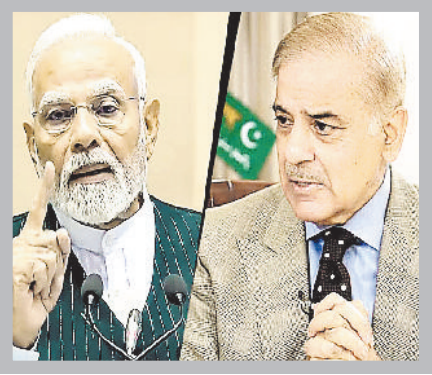
ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय किराया वहनीयता योजना समाप्त

ऑस्ट्रेलिया का वित्तीय वर्ष एक जुलाई को समाप्त हो गया और इसी के साथ 'राष्ट्रीय किराया वहनीयता योजना' भी समाप्त हो गई, जिसके तहत देश भर में 35,000 से ज्यादा किरायेती किराए के घर उपलब्ध कराए गए थे। यह योजना 2008 में रड सरकार ने घरी के महंगे होते जाने की समस्या के मद्देनजर शुरू की थी। लेकिन बाद में 2014 में एबॉट सरकार ने इसे बंद कर दिया और 2016 के बाद किसी भी नए घर को इसके तहत मंजूरी नहीं दी गई। इस जून में, आखिरी 3,600 संपत्तियां भी इस योजना के दायरे से बाहर हो गई हैं। आखिरकार, इस योजना ने अपने कुछ मुख्य वादे पूरे किए। इसने काफी कम समय में किरायेती किराए के घरों की आपूर्ति बढ़ाई और ऐसे घर बनाए जो इसके बिना नहीं बन पाते। लेकिन इसके आलोचक भी रहे हैं, जिन्होंने इसे लागू करने के तरीके और इसके नतीजों में कई कमियां गिनाईं। तो, पीछे मुड़कर देखें तो इस अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? और क्या सरकार ने इस योजना के बंद होने से आई रिक्तता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? हाशिये पर रह रहे समूह के लिए सस्ता किराया इस योजना के तहत डेवलपर्स को किरायेती किराये के घर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया।



का इस्तेमाल कर चलना फायदेमंद हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से चलने से रक्तचाप और ग्लूकोज सहनशीलता जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार होता है। हालिया शोध में प्रतिदिन करीब 7,000 कदम चलने को कई बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त लक्ष्य बताया गया है। शोध यह भी बताते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय छोटे-छोटे अंतराल में बार-बार चलना या हल्की गतिविधि करना एक बार में लंबी सैर से अधिक लाभकारी हो सकता है।

आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो सकती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक मजबूरी का अर्थ यह नहीं कि पाकिस्तान की नीतियों में स्थायी परिवर्तन आ गया है। यदि आतंकवाद को समर्थन देने की उसकी सोच में बदलाव नहीं आता तो केवल व्यापार या परिवहन सेवाएं शुरू कर देने से स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी महाशक्ति केवल मानवीय आधार पर हस्तक्षेप नहीं करती। हर देश अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका



लंबे समय से यह चाहता रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव क्षेत्र में न चला जाए। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और दोनों देशों की बढ़ती सामरिक साझेदारी अमेरिका के लिए चिंता का विषय रही है। ऐसे में यदि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद को बढ़ावा देता है तो उसके पीछे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने और पाकिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने की रणनीति भी हो सकती है। ट्रम्प यदि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की बहाली का श्रेय लेना चाहते हैं तो यह उनकी राजनीतिक और रणनीतिक सोच का हिस्सा हो सकता है। लेकिन भारत को किसी भी बाहरी दबाव या अंतरराष्ट्रीय छवि के कारण अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत यही रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने, सीमा पार घुसपैठ रोकने और भारत विरोधी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए ठोस और विश्वसनीय कदम नहीं उठाता, तो केवल वार्ता के नाम पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विश्वास का है। विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है। पाकिस्तान ने

अतीत में अनेक बार आश्वासन दिए, लेकिन उसके बाद भी आतंकी घटनाएं होती रहीं। जब तक वह अपने आचरण से यह साबित नहीं करता कि उसने आतंकवाद को स्थायी रूप से त्याग दिया है, तब तक किसी भी व्यापक संबंध बहाली का आधार कमजोर ही रहेगा। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ने से कट्टरता कम होगी और शांति को मजबूती मिलेगी। यह विचार सिद्धांत रूप में आकर्षक लगता है, लेकिन व्यवहार में इसकी सफलता तभी संभव है, जब दोनों पक्ष समान ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। यदि एक देश शांति की बात करे और दूसरा आतंकवाद को संरक्षण देता रहे तो ऐसे प्रयास अंततः फिफल हो जाते हैं। इसलिए भारत को किसी भी नई पहल से पहले स्पष्ट शर्त रखनी चाहिए कि आतंकवाद और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते। भारत ने हमेशा मानवीय मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। चाहे कैदियों की रिहाई का विषय हो, धार्मिक यात्राओं की सुविधा हो या प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता का प्रश्न, भारत ने उदारता दिखाई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर किसी प्रकार की हिलाई उचित नहीं हो सकती। भारत आज विश्व की तेजी से उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है।

ऐसे समय में उसे भावनात्मक निर्णयों के बजाय दूरदर्शी और यथार्थवादी नीति अपनानी होगी। यदि पाकिस्तान वास्तव में संबंध सुधारना चाहता है तो उसे केवल संवाद की अपील करने के बजाय आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करके अपनी नीयत साबित करनी होगी। यही वह कसौटी है जिस पर भविष्य के किसी भी संबंध की सफलता निर्भर करेगी। अंततः भारत शांति का समर्थक है, लेकिन शांति की कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। मित्रता वहीं टिकाऊ होती है जहां विश्वास, पारदर्शिता और ईमानदारी हो। पाकिस्तान का अब तक का इतिहास इन तीनों मानकों पर संतोषजनक नहीं रहा है। इसलिए भारत को हर प्रस्ताव का स्वागत खुले मन से अवश्य करना चाहिए, लेकिन निर्णय केवल अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। यदि पाकिस्तान अपने व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाता है तो दक्षिण एशिया में स्थायी शांति का मार्ग अवश्य प्रशस्त हो सकता है। यदि अतीत की गलतियां दोहराई जाती हैं तो इतिहास एक बार फिर यह सिद्ध करेगा कि केवल संवाद की इच्छा पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए भरोसेमंद आचरण भी उतना ही आवश्यक होता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर आपकी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

स्वयं के धर्म की चिंता

एक आदमी तालाब के किनारे बैठ कर कुछ सोच रहा था। तभी उसने पानी में किसी के डूबने की आवाज सुनी और उसने तालाब की तरफ देखा तो उसे एक बिच्छू तालाब में डूबता दिखाई दिया। अचानक ही वह आदमी उठा और तालाब में कूद गया। उस बिच्छू को बचाने के लिए उसने उसे पकड़ लिया और तालाब के बाहर लाने लगा। इससे घबराकर बिच्छू ने उस आदमी को डंक मारा। आदमी का हाथ खून से भर गया वो गिर-जोर से चिल्लाने लगा, उसका हाथ खुल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। आदमी फिर उसके पीछे गया। उसने बिच्छू को पकड़ा। लेकिन बिच्छू ने फिर से उसे काट लिया। यह बार-बार होता रहा। यह पूरी घटना दूर बैठा एक आदमी देख रहा था। वो उस आदमी के पास आया और बोला - अरे भाई ! वह बिच्छू तुम्हे बार-बार काट रहा है। तुम उसे बचाना चाहते हो, वो तुम्हे ही डंक मार रहा है। तुम उसे जाने क्यूँ नहीं देते? भर रहा है अपनी मौत, तुम क्यूँ अपना खून बहा रहे हो? तब उस आदमी ने उत्तर दिया - भाई ! डंक मरना तो बिच्छू की प्रकृति है। वह वही कर रहा है लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, और मेरा धर्म है दूसरों की सेवा करना और मुसीबत में उनका साथ देना। अतः बिच्छू अपना धर्म निभा रहा है और मैं मेरा।

टैंड

इफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव

केटीय नॉर्मंडल की बैठक में 7,145 करोड़ रुपये की लागत वाले कानपुर-काबई एक्सप्रेस-कंट्रोल्ड बीनफील्ड हाइवे के निर्माण को त्वरित दी गई है। यह फैसला भारत के इफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की दिशा में एक और अमल कदम है।

- राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

नई संभावनाएं

यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। पहली बार, राज्य से ताजी चेरी और आलुबुखारे की खेप ओमान पहुंची है। ओमान में हिमाचल के फलों को मिली सराहना ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।

-सुखविंदर सिंह सुखु, सीएम, हिमाचल प्रदेश

अत्यंत दुखद

बेगलूर में मद्राप्रधान की पत्थर की खदान में हुए भीषण हादसे में विहार के हजारी मजदूर भाइयों के असमय निधन की खबर अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को उनके पवित्र चरणों में स्थान मिले।

- सभाट चौधरी, सीएम, बिहार

सत्ता का गलत इस्तेमाल

बीजेपी अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करके बीजेपी-शासित राज्यों, खासकर परिचय बंगाल में राजनीतिक हिंसा का खराब नमूना बना रही है और पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। जनता इस नकारात्मक व्यवहार से बेहद आक्रोशित है।

-अश्विनीश यादव, सांसद, राण

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

रिंग रोड नं. 2, गौरवपथ, बिलासपुर
फोन: 401050, 271016, फैक्स-271018
ई-मेल: haribhoomibsp@gmail.com
वेब-साइट: www.haribhoomi.com

राजधानी कीव पर भीषण मिसाइल व ड्रोन हमला, 17 की मौत

कीव। रूस ने बुधस्पतिवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक अन्य घायल हो गए। हमलों के दौरान कई घंटों तक राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। रूस ने इस हमले को यूक्रेन की ओर से मौस्को के तेल प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों का 'प्रतिशोध' बताया है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ा है। बैलिस्टिक और कूज मिसाइलों तथा



रूस ने मास्को में हमले का लिया 'प्रतिशोध'

ड्रोन से किए गए इस हमले में राजधानी के कई हिस्सों में आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।

रूस ने दागी 74 मिसाइलें, 496 ड्रोन

यूक्रेन की वायु सेना के अनुसार, रूस ने इस हमले में 74 मिसाइलें दागीं, जिनमें 24 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के 496 ड्रोन भी छोड़े गए। इस बीच, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि उसकी सेना ने रातभर चले अभियान में मौस्को के पूर्व में स्थित निजनी वोवगोरोद क्षेत्र की रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। जनरल स्टाफ ने यह भी दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले लुहान्स्क क्षेत्र में सिवेरुकी दोनेत्स नदी पर बने एक रेलवे पुल को भी निशाना बनाया। उसके अनुसार, रूसी सेना इस पुल का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों और अन्य सामग्री की आवाजाही के लिए कर रही थी।

अयोध्या बार एसोसिएशन ने थाना प्रभारी राम जन्मभूमि को सौंपा शिकायती पत्र

‘चंपत को बचाया जा रहा, गिरफ्तारी हो’ अयोध्या के वकीलों ने किया बड़ा प्रदर्शन

राम मंदिर दान चोरी मामले : पुलिस और वकीलों के बीच हुई धक्का-मुक्की

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित दान राशि चोरी मामले को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपना ज्ञापन थाना प्रभारी राम जन्मभूमि को सौंपकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और विरोध दायर करने की मांग की है। उनका आरोप है कि मामले के निम्नोदर लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है और मामले में आरोपी की कार्यवाई की जा रही है।

एजेंसी ►► अयोध्या

राम मंदिर दान मामले को लेकर अयोध्या में वकीलों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जब सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता कचहरी परिसर से जुलूस निकालकर राम पथ की ओर बढ़े. इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी वकीलों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ जगहों पर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे वकील थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर राम



मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। वकील

और पुलिस बल में गहमागहमी के बीच लॉयर्स का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचा और संबंधित ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ तहरीर सौंपी। इसके बाद प्रदर्शनकारी वकीलों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि 'आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है।' उन्होंने चेतावनी दी कि 'अगर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।'

‘चंपत और अनिल ने फंसाया’ टिन्नु के भाई का बड़ा आरोप

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नु यादव के भाई दिनेश यादव ने पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया। दिनेश ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर अपने भाई को फंसाने का सीधा आरोप लगाया है। दिनेश ने टिन्नु को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि बड़े पदाधिकारी खुद को बचाने के लिए उसे मोहरा बना रहे हैं।



दिनेश ने कहा कि उनका भाई पिछले 20 सालों से चंपत राय के साथ काम कर रहा था। टिन्नु का स्वभाव बहुत अच्छा है और उस पर कोई मुकदमा नहीं है। दिनेश ने आरोप लगाया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। बड़े लोग खुद बचने के लिए टिन्नु को फंसा रहे हैं क्योंकि दान पेटी की एक चाबी टिन्नु और दूसरी बैंक कर्मियों के पास होती थी।

नाव पलटने से छह पर्यटकों की मौत, तीन लोग लापता

पेशावर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक झील में नाव पलटने से एक ही परिवार के कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य सदस्य लापता हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हादसा अपर स्वात जिले की कलाम घाटी स्थित सैफुल्ला झील में हुआ। सैफुल्ला झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पुलिस के अनुसार, झील में सैर के दौरान नाव में सवार सभी नौ यात्री एक ही परिवार के सदस्य थे। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद 'रेस्क्यू 1122 स्वात' की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

सूचना

ग्राम पंचायत महारानीपुर (देऊरगढ़ारा) बेलडांड के किसानों द्वारा शिकायत किया गया है, जिसमें लाईनमैन चन्द्रकुमार सिदार के द्वारा कार्यालय वितरण केन्द्र राजापुर में पदस्थ रहने के दौरान सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर 7000.00 रुपये एवं उससे अधिक की राशि लिया गया है, इसकी शिकायत की गई थी, जिसकी जांच करने पर चन्द्रकुमार सिदार परि० श्रे०-1(ला.) के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम- महारानीपुर (देऊरगढ़ारा एवं चिड़ापारा) के ग्रामीणों से कृषि पंप कनेक्शन के नाम पर अवैध राशि की वसुली किया जाना सही पाया गया है। तथा कार्यवाही करते हुए कार्यालय यंत्री (सं/स) संभाग अम्बिकापुर के द्वारा चन्द्रकुमार सिदार परि० श्रे०-1 (ला.) को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छ०म० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन कर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर बलरामपुर वितरण केन्द्र में पदस्थ किया गया है।

कार्यालयन यंत्री (सं/स) संभाग छ.स्ट.पॉ.डि.कं. लिमि. अधिकारपुर

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA DISTT - RAIGARH (C.G)

No./654/NIT/2026 - 27 Notice Inviting tender 3rd Call GHARGHODA Dated 30/06/2026 Chief Municipal Officer invites Online Tenders on behalf of Nagar Panchayat GHARGHODA for providing labour (C.G. Contract labour Act 1690 & 1969) in Percentage Rate in form A from Eligible class Registered contractors in 'Unified Registration System e-Registration' PWD Chhattisgarh/Registered firms and their undertaking on UADD website https://eproc.cgstate.gov.in

System Tender No.	Name of work	Estimated cost (in Lacs)	Earnest Money Deposit	Tender Form Fees	Time Period of Completion
194536	Construction of B.T. Road in Ward No. 07 Suraj Sharma house to Raja Badhai house and Kailash Mishra house to Hemlal	Rs 13.39	Rs.10100/- (EMD in Favour of CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	750/- DD at (Payable to CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	Construction Period - 06 month (from the date of Work Order) including rainy season
194541	Construction of B.T. Road in Ward No. 13 Atal Parisar to Vikash Sharma house.	15.93	Rs.12000/- (EMD in Favour of CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	750/- DD at (Payable to CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	Period - 06 month (from the date of Work Order) including rainy season
194544	Construction of B.T. Road in Ward No. 14 Sani Temple To Mata Temple, Jayant Panda house.	Rs 16.24	Rs.12200/- (EMD in Favour of CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	750/- DD at (Payable to CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	Period - 06 month (from the date of Work Order) including rainy season
194549	Revamping of Material Recovery Facility (MRF) including installation of Machinery and construction of Compost Plant in Municipal Areas of GHARGHODA Chhattisgarh	Rs 32.64 (Sor-27.59) (Non Sor-5.05)	Rs.16400/- (EMD in Favour of CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	10000/- DD at (Payable to CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	Construction Period - 06 month (from the date of Work Order) including rainy season Trail run 03 Months.
194556	Construction of a Cultural Hall for Kanwar Community in Nagar Panchayat Gharghoda (1st Call)	Rs 25.00	Rs.18800/- (EMD in Favour of CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	750/- DD at (Payable to CHIEF MUNICIPAL OFFICER, NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA)	Period - 12 month (from the date of Work Order) including rainy season

Chief Municipal Officer NAGAR PANCHAYAT, GHARGHODA

12वीं कंपार्टमेंट की तारीख बदली अब 28 जुलाई को एग्जाम

एजेंसी ►► नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीबीएसई की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 12वीं का कंपार्टमेंट एग्जाम 28 जुलाई को होगा। पहले 15 जुलाई को सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम प्रस्तावित था। सीबीएसई ने आवेदन पोर्टल शुरू कर दिया है। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं, कंपार्टमेंट एग्जाम की तारीख में हुए बदलाव से स्टूडेंट्स नाराज हैं।



संगम पोर्टल के जरिए होगा आवेदन

सीबीएसई ने 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्कूलों को एलओसी जमा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 8 जुलाई तक का समय दिया गया है। 8 जुलाई रात 11:59 बजे तक एलओसी जमा करवाई जा सकती है। हालांकि, स्टूडेंट्स व्यक्तिगत स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं।

कंपार्टमेंट एग्जाम की फीस

कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए निर्धारित फीस की बात करें तो भारत के स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपये फीस निर्धारित है। वहीं, नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए 1100 रुपये और भारत से बाहर के देशों के स्टूडेंट्स के लिए 2200 रुपये फीस निर्धारित है। दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को एग्जाम फीस से छूट दी गई है।

बिना ऑर्डर के गिराई 80 झुगियां, 5 अधिकारी सस्पेंड

सूरत। गुजरात के सूरत नगर निगम ने नासिरनगर इलाके में करीब 80 झुगियों को 'रहस्यमयी' तरीके से गिराने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने अपने पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कुछ दिन पहले ही निगम ने इस डिमोलिशन में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया था। बताया गया कि 30 मई को हुई इस घटना की जांच के लिए इंटरनल कमेटी बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब इन अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। एसएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने पहले कहा था कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, निगम के अधिकारी वहां सिर्फ रोड डिमांडेशन के लिए गए थे।

नारी स्वास्थ्य समस्याओं में भरोसेमंद

कमर-पेड़ू में दर्द, खून की कमी, कमजोरी, हथेली-तलवों में जलन, हार्मोन्स असंतुलन चिड़चिड़ापन आदि कठिन समस्याओं में सहायक

हेमापुष्पा

Helpline: 011-23261111, rajvaidyacare@gmail.com

संगठन में बदलाव से नाराज सांसद तिवारी छोड़ने जा रहे कांग्रेस!

एजेंसी ►► नई दिल्ली



पंजाब कांग्रेस में छिड़ी रात

पंजाब कांग्रेस को संगठनात्मक फेरबदल के बाद बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान की ओर से गठित की गई चुनावी समितियों से चंडीगढ़ के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी को बाहर रखा गया है। इस पर मनीष तिवारी की नाराजगी खुलकर बाहर आई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। मनीष तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल इस पार्टी को दिए हैं, लेकिन आज कुछ लोगों की असुरक्षा की भावना के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। उनके इस बयान के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चचाएं हैं कि मनीष तिवारी पार्टी छोड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए पंजाब में यह बड़ा झटका होगा।

‘विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं’

नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को शरणार्थी कहना सही नहीं है। वे 'संघर्ष के योद्धा' थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों की बनाई जमीन, कारोबार और संपत्ति छोड़कर भारत को चुना। उन्होंने कहा कि ये लोग इसलिए भारत आए, क्योंकि यहां बिना डर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। भारत को एक रखने की लड़ाई हम सब हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। भागवत ने नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह में ये बातें कही।

LIC HFI
LIC HOUSING FINANCE LTD.

एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.

प्रथम तल, भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, मंगरपारा
रोड, बिलासपुर - 495001 (छ.ग.) फ़ोन: 07752-418136

परिशिष्ट - IV नियम 8 (1) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

अधोस्तावर एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि. का अधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय अधिकारों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रस्तुत गतिव्यों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित ऋणारियों का व्याज राशि सहित नोटिस प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन की समयवधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋण ग्रहीत राशि का भुगतान करने में असफल रहा है अतः ऋण ग्रहीत और सर्वसाधारण को पुनर् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोस्तावरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) पर्यन्त उक्त नियम (8) के साथ पत्रा जाये एतद्विषय नीचे वर्णित संपत्ति का आधिपत्य को ग्रहण कर लिया गया है। ऋण ग्रहीत को विनिर्दिष्ट और सर्वसाधारण को सामान्यतः पुनर् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर व्याज के लिये निम्न खाते के सामने अंकित एलआईसी हाऊसिंग लि. बिलासपुर प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	खातेदार का नाम	संपत्ति विवरण	मांग सूचना पत्र में उल्लेखित राशि कलमा तिथि	मांग सूचना पत्र में
1)	उधारकर्ता- श्री त्रिलोकचंद मिरी, सह-उधारकर्ता- श्रीमती कांछा मिरी, ऋण खाता संख्या 120200005999/120200006361	खसरा नं. 1485/18 शामिल है (बी/1) के अनुसार खसरा नं. 1485/34/1, प.ह. नं. 4, ग्राम बांधा, कैलाश नगर, विकासखंड बाहन्नीडीह, आरएलएम बांधा, वार्ड नंबर 17, रेलवे कॉलोनी वार्ड (PH. रोड), तहसील बांधा, जाल्जौर बांधा (छ.ग.) 495671 में क्षेत्रफल 1308 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश। सीमार्: उत्तर - सड़क, दक्षिण - श्री ओम प्रकाश देवागन की भूमि, पूर्व - विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम - विक्रेता की शेष भूमि।	13.11.2025 30.06.2026	₹ 14,87,656.00 + व्याज व अन्य चार्ज

वैधानिक सूचना: ऋणी एवं जमानतदार को सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के छपने की तारीख के 30 दिनों के अंदर, वे उपरोक्त राशि एवं उस पर देय व्याज एवं चार्जों का भुगतान कर दें अन्यथा उक्त वर्णित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा उसके बाद ऋण एवं व्याज की वसूली खर्च सहित ऋणी एवं जमानतदारों से की जायेगी।

दिनांक: 03.07.2026, स्थान: बिलासपुर

प्राधिकृत अधिकारी



डा.ऑर्थो

Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

अब दर्द भी घुटने टकेगा

विनिवेश ने पकड़ी रफ्तार, पहली तिमाही में बजट लक्ष्य का 31 प्रतिशत राजस्व जुटाया

एजेंसी ►► नई दिल्ली

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रिकरण की रफ्तार तेज कर दी है और पहली तिमाही में ही समूचे वित्त वर्ष के बजट लक्ष्य का करीब 31 प्रतिशत जुटा लिया है। यह किसी भी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विनिवेश प्रक्रिया की अब तक की सबसे तेज प्रगति मानी जा रही है।

सरकार मई के मध्य से जून के बीच लगभग हर सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी (पीएसयू) में हिस्सेदारी बेचने के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) लेकर आई। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के छह प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने कुल 18,561 करोड़ रुपये जुटाए।

आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार में दूसरे दिन तेजी

एजेंसी ►► मुंबई

स्थानीय शेयर बाजारों में बुधस्मतिवार को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही और दोनों मानक सूचकांक लाभ में रहे। कच्चे तेल के दाम में गिरावट, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक घटनाक्रमों और आईटी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 579 अंक चढ़ा जबकि एनएसई निफ्टी में 170 अंक की तेजी रही।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 579.48 अंक बढ़कर 77,502.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 656.29 अंक चढ़कर 77,578.93 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी 169.85 अंक की तेजी के साथ 24,175.70 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस 5.64 प्रतिशत चढ़ा। इसके बाद

खबर संक्षेप

सुजुकी मोटरसाइकिल की बिक्री में 21 फीसदी इजाफा



मुंबई। जापान की दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी सुजुकी इंडिया की जून में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 1,15,030 इकाई हो गई। कंपनी ने जून 2025 में कुल 95,244 दोपहिया वाहन बेचे थे। घरेलू बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 91,264 इकाई रही, जो एक वर्ष पहले इसी महीने 73,934 इकाई थी। वहीं, समीक्षाधीन महीने में निर्यात 21,310 इकाई के मुकाबले सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 23,766 इकाई हो गया।

एनबीसीसी ने 955 करोड़ रुपए के निर्माण ठेके दिए



नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए 955.13 करोड़ रुपये के ठेके दिए हैं। कंपनी ने बुधस्मतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान उसने 955.13 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के ठेके प्रदान किए। एनबीसीसी ने पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कुल नौ ठेके दिए।

जी एंटरटेनमेंट वॉरंट जारी कर 3143 करोड़ जुटाएगी

नई दिल्ली। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने प्रवर्तक समूह को इकाई



को पूर्ण परिवर्तनीय वॉरंट जारी कर 3,143.51 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 126 रुपये प्रति वॉरंट के निर्गम मूल्य पर 24.95 करोड़ तक पूर्ण रूप से परिवर्तनीय वॉरंट जारी करने की मंजूरी दी है। कंपनी में प्रवर्तक समूह की इस इकाई की हिस्सेदारी थीं, 2026 तक 3.99 प्रतिशत थीं।



इनविट के जरिए 6,367 करोड़ प्राप्त हुए

यह हिस्सेदारी बिक्री सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, जीआईसी और आईआरएफसी में की गई। इसके अलावा, अवसरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के जरिये परिसंपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने से भी 6.367 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस तरह विनिवेश एवं मौद्रिकरण के जरिये अब तक कुल 24,928 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 80,000 करोड़

रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

सब्सिडी खर्च बढ़ने की आशंका

पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा और उर्वरक आयात महंगा होने से सब्सिडी खर्च बढ़ने की आशंका है। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में ही राजकोषीय घाटा 1.62 लाख करोड़ रुपये, यानी वार्षिक लक्ष्य का 9.6 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। मई तक शुद्ध कर राजस्व जहां सालाना लक्ष्य का 12.1 प्रतिशत रहा, वहीं गैर-कर राजस्व (जैसे विनिवेश) 17 प्रतिशत तक पहुंच गया।

सरकार ने तैयार की विनिवेश की रूपरेखा

सरकार ने आगे भी सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश की रूपरेखा तैयार कर ली है और उम्मीद है कि वह तय लक्ष्य को पार कर सकती है। इस साल का सबसे बड़ा विनिवेश भारतीय जल बोमा निगम (एलआईसी) में हो सकता है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19अटल नगर नवा रायपुर

क्रमांक / ESTB-101(3)/30/2026-DHS/379
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/06/2026

संशोधित सूचना पत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के पत्र क्रमांक/ ESTB-101(3)/30/2026-DHS/346 दिनांक 16.06.2026 के द्वारा संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य सेंजोक्त पुरुष/महिला, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 वाई बॉय एवं वाई आया) के कुल 550 पदों पर अभ्यार्थियों को कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त 01 वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के चयन हेतु कोविड-19 के 10 बोनस अंको का लाभ किये जाने हेतु अंतिम अवसर देते हुये दिनांक 30.06.2026 तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर करने हेतु संशोधित सूचना पत्र जारी किया गया था।

उक्त संशोधित सूचना में संशोधित करते हुये अभ्यार्थियों को दिनांक 10.07.2026 तक कोविड-19 के 10 बोनस अंक हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जा सकता है। टीप:-कोविड बोनस अंक हेतु आवेदन दिनांक 10.07.2026 तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।

आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक (अधिज्ञाप)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

जी-262701856/2

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की खबरों की संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन नं. 0771-2512580, 81, email: cgsamvad@gmail.com

क्रमांक 1198/छ.ग.सं. / प्रका. / 2026

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/07/2026

विभिन्न सामग्रियों के मुद्रण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मा के इमैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा विभिन्न सामग्रियों “अ”, “ब”, “स” श्रेणी एवं वेब ऑफसेट मुद्रण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मा के इमैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरें हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदा	प्री-बिड मीटिंग (3:30 बजे अपराह्न) (प्री-बिड सुझाव दिनांक 10072026 तक अनिवार्यतः ईमेल के माध्यम से ही जमा किया जाना है)	निविदा प्रपत्र (बिना ब्याज के) (GST वापसी योग्य) सहित वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के) (वापसी योग्य)	निविदा राशि लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि (2:00 बजे अपराह्न तक)	ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (3:00 बजे अपराह्न तक)	निविदा खोलने की तिथि (4:0 बजे अपराह्न से)
1	मुद्रण “अ” श्रेणी	08-07-2026	5,900/-	5,00,000/-	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026
2	मुद्रण “ब” श्रेणी	08-07-2026	2,360/-	50,000/-	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026
3	मुद्रण “स” श्रेणी	08-07-2026	590/-	5,000/-	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026
4	वेब ऑफसेट मुद्रण	08-07-2026	5,900/-	5,00,000/-	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026

मुख्य कार्यपालन

सं. 48335

अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 25.06.2026

(ई-प्रोक्वोरमेंट निविदा सूचना) (प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यापाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र “अ” में प्रतिशत दर पर दिनांक 15.07.2026 तक आमंत्रित की जाती है:-

निविदा आमंत्रण सू. क्र./सि.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
210/194375	शासकीय महाविद्यालय उत्तई जिला दुर्ग में अतिरिक्त कक्ष का शेष निर्माण कार्य	85.23
211/194377	लाईवलीलीहूड कॉलेज दुर्ग में 50 सीटर बालक छात्रावास सहवीकीदार आवास गृह का शेष निर्माण कार्य	29.81
212/194378	खैरागढ़ संभाग के राज्य मार्ग पर जंक्शन सुधार एवं कैश बेरियर लगाने का कार्य	176.92
213/194379	लोक निर्माण विभाग, संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न राज्य मार्ग पर कैश बेरियर लगाने का कार्य	172.53
214/194380	लोक निर्माण विभाग, संभाग बालोद के अंतर्गत विभिन्न राज्य मार्ग पर जंक्शन सुधार का कार्य	77.93
215/194381	लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग क्र. 01 के अंतर्गत कार्यालय डिवीजनए कमलादेवी महाविद्यालय, एवं 100 सीटर विस्तार गर्ल्स हॉस्टल भवन राजनादगांव का रंगाई पोताई का कार्य (जोनल एजेंसी)	15.07
216/194382	उपसंभाग क्र. 02 राजनादगांव के अंतर्गत शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरागांव में रंगाई पोताई का कार्य (जोनल एजेंसी)	14.05
217/194383	उपसंभाग क्र. 01 राजनादगांव विभिन्न एफ टाईप आवाससमूहों में का रंगाई पोताई का कार्य (जोनल एजेंसी)	11.70
218/194384	उपसंभाग डोंगरागढ़ के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के पुल-पुलियाँ का विशेष मरम्मत कार्य (जोनल एजेंसी)	30.00
219/194385	उपसंभाग क्र. 01 राजनादगांव अंतर्गत पुराना कंपोजिट भवन, न्यू सॉफ्ट हॉउस एवं पुराना सॉफ्ट में रंगाई-पोताई का कार्य (जोनल एजेंसी)	40.81
220/194386	उपसंभाग क्र. 01 बालोद के अंतर्गत विभिन्न गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं रंगरोगन का कार्य (जोनल एजेंसी)	15.75

टीप:- 1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञापि, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्वोरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट <http://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है। 2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

अधीक्षक अभियंता

लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग

जी-262701845/3

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER P.W.D. (B&R) AMBIKPUR CIRCLE AMBIKAPUR

Invitation Date :- 26.06.2026

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

01. For tender detail please visit <http://eproc.cgs.tate.gov.in>
02. Concern Division - S.No. 01 to 06 Ambikapur and S. No. 07 Jashpur Division
03. S.No. 01,02 - ‘C’ Class And Above Contractor S.No. 03 to 07 - ‘D’ And Above Contractor
04. Bid Submission Due Date - 20.07.2026

S. No.	N.I.T. No.	Name of work	P.A.C. in lacks
1	115	Construction of Transit Hostel (Teacher Qtr.) for Three Unit Building at Udaipur Distt. Surguja (C.G.) including Electrification (First Call)	126.23
2	116	Construction of Transit Hostel (Teacher Qtr.) for Three Unit Building at Narmadapur Mainpat Distt. Surguja (C.G.) including Electrification (First Call)	126.23
3	117	Construction of Store (Hall) in Sainik School Ambikapur Distt. Surguja (C.G.) (First Call)	35.93
4	118	Seepage Repairing Works (Water Proofing Treatment) of Various Building at Sainik School Ambikapur Distt. Surguja (C.G.) (First Call)	47.69
5	119	BT Renewal work for External and Internal Approach Roads at Sainik School Ambikapur Distt. Surguja (C.G.) (First Call)	99.00
6	120	Repairing of Boundrywall of Sainik School Ambikapur Distt. Surguja (C.G.) (First Call)	12.78
7	121	Construction of Fire Station Building and Garage at Distt. Jashpur (C.G.) (First Call)	96.86

SUPERINTENDING ENGINEER

जी. 262701829/5 P.W.D. (B&R) AMBIKPUR CIRCLE AMBIKAPUR

एपीजे सुरेंद्र पार्क को 41 करोड़ का आयकर नोटिस जारी



नई दिल्ली। द पार्क और प्लूरिज जैसे ब्रांड के स्वामित्व वाली एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड को आयकर विभाग से वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज सहित 41.06 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस जारी किया गया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह आदेश विस्तृत जांच के बाद किए गए आकलन से संबंधित है और इसमें आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुछ आय को जोड़ा गया तथा कुछ व्यय को अस्वीकृत किया गया है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड ने बुधवार देर रात कहा, “हम निश्चित रूप से इस मांग के गौरव इस आदेश के खिलाफ उपयुक्त अपीलीय प्राधिकरण/वेबिनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएससी) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं।”

कार्यालय नगर पालिका परिषद कटघोरा, जिला-कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक / 775 / तक्र0 शा0 / न0पा0पा0/2026

कटघोरा, दिनांक 02/07/2026

ई-प्रोक्वोरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

Chief Municipal Officer, Katghora Municipal Council invites Online Tenders for and on behalf of Municipal council Katghora for S.O.R. percentage rate & SOR C.G. PWD Building 20.04.2026 ELECIRICAL 10.04.2026 /PHE SOR 01/06/2020 tender in FORM- 'A' from eligible class -contractors of PWD Chhattisgarh. e-Procurement System (<https://eproc.cgstate.gov.in>)

S. N.	System Tender N. & Date	Description	Total Estimate Cost Rs. In Lacs	Last Date Online Submission	Remark
1.	194489	वाई क. 02 नवीन कार्यालय भवन परिसर में शौचालय कोमलैक्स निर्माण कार्य	48.16	23/07/2026	1st Call

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु ई-प्रोक्वोरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> में तथा कार्यालयीन समय पर नगर पालिका परिषद कटघोरा से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कटघोरा

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बेमेतरा

ज्ञाप क्रं. 3897/ व.ले.लि./2025-26/ बेमेतरा, दिनांक :- 01/07/26

रुचि की अभिव्यक्ति

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण की आमसभा, व्ही.आई.पी. कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों इत्यादि हेतु टेन्ट, पण्डाल, मंच इत्यादि के आयोजन व्यवस्था संपादित किया जाता है। वर्ष 2026-27 में इस कार्यालय द्वारा संपादित किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों हेतु योग्य टेन्ट हाऊस प्रतिष्ठानों की सूची तैयार किये जाने तथा आयटमों के दर निर्धारण हेतु इच्छुक अनुभवधारी एवं अर्हताधारी टेन्ट हाऊस प्रतिष्ठानों से सहमति तथा आयटमवार दर प्रस्तुत करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है।

विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :-14/07/2026
2. दर प्रस्तुत करने की तिथि :-21/07/2026
3. दर खोलने की तिथि :-22/07/2026

अभिव्यक्ति आमंत्रण प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवश्यक अर्हताएं :-

1. टेन्ट हाऊस प्रतिष्ठान के मालिकाना तथा लाईसंस की प्रति होना चाहिये।
2. जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति।
3. टेन्ट हाऊस प्रतिष्ठान का विगत 05 वर्षों में टेन्ट हाऊस कार्यक्रम संपादन औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रु. 1.00 करोड़ होना आवश्यक है, तत्सम्बंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4- विगत 05 वर्षों में छ.ग. राज्य में संपादित महत्वपूर्ण कम से कम 03 व्ही.आई.पी. कार्यक्रम संपादित किये जाने जिसमें प्रति कार्य के लागत कम से कम रु. 1.00 करोड़ होने का अनुभव प्रमाण-पत्र, जो कार्यपालन अभियंता / समकक्ष अथवा उच्च अधिकारी से हस्ताक्षरित हो।

विस्तृत शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता

लौ.नि.वि. (भ/स) संभाग बेमेतरा

जी-262701851/3

आईवीएफ फेल होने के बाद भी निराश न हों : माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर



तकनीक तथा सही समय पर एम्बियो ट्रांसफर की सहायता से दंपति का सफल गर्भधारण संभव हो सका। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के विशेषज्ञ डॉ. प्रतिभा माखीजा का कहना है कि आईवीएफ असफल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भ्रूण की गुणवत्ता, गर्भाशय की स्थिति, हार्मोनल असंतुलन, शुक्राणुओं की समस्या या इम्प्लंटेशन में कठिनाई। इन कारणों को सही पहचान और उचित

उपचार से अगली आईवीएफ प्रक्रिया को सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि पहले आईवीएफ में सफलता नहीं मिली है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मरीज की स्थिति अलग होती है और सही उपचार के साथ कई दंपति सफलतापूर्वक माता-पिता बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। अक्सरने चौक के पास स्थित माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आईवीएफ, आईसीएसआई ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, पुरुष एवं महिला बांझापन की जांच एवं उपचार सहित अत्याधुनिक फर्टिलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां प्रत्येक मरीज के लिए व्यक्तिगत उपचार योजना बनाकर बेहतर परिणाम देने का प्रयास किया जाता है। अधिक जानकारी के 8085758585 संपर्क करें।

C/PDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छ.ग. शासन का एक उद्यम) (छ.ग.वि.मं. की उत्तरदायी कंपनी)

सी.आई.एन. - U40108 CT2003 SGC015822

कार्या. - कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग-दो, पश्चिम, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07752-427091 वेबसाइट: www.cspdcl.co.in, टेलीफोन नं0: 07752.427091

क्रमांक / क030 / न0रं0पा0 / साम0 / 1111

बिलासपुर, दिनांक 02.07.2026

बिजली बंद की सूचना

समस्त सम्माननीय उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि निर्माण कार्य एवं ख-रखाव का कार्य किये जाने हेतु तात्काल में द्वापैर गये क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बंद रहेगा, आवश्यकतानुसार समायोजित घटिया। बह्या जा सकता है।

क्र.	समय	दिनांक/दिन	उपकेंद्र	फीडर	प्रभावित क्षेत्र
1	सुबह 10:00 से 02:00 बजे	03.07.2026 शुक्रवार	33/11 के0व्ही 0 उत्तरापुर रेलवे स्टेशन उपकेंद्र	11 के0 व्ही 0 उत्तरापुर ओवरक्रॉस फीडर	उत्तरापुर रेलवे स्टेशन, रैन दयाल आवासीय कॉलोनी एवं आसपास का क्षेत्र।
2	सुबह 10:00 से 02:00 बजे	04.07.2026 शनिवार	33/11 केव्ही कोनी उपकेंद्र	11 के0 व्ही 0 लोखण्डी फीडर	लोखंडी, घुरी पारा, ग्राम पंचायत मंगला एवं आसपास का क्षेत्र।
3	सुबह 09:00 से 02:00 बजे	06.07.2026 सोमवार	33/11 केव्ही चांदीडीह उपकेंद्र	11 के0 व्ही 0 बिरकोना फीडर	बड़ा कोना, साई मंदिर, एवं आसपास का क्षेत्र।
				11 के0 व्ही 0 सरकम्पा फीडर	सरस्वती शिशु मंदिर, जौरा तालाब, जिला अस्पताल, सौपन चौक, बंगालीपारा, एवं आसपास का क्षेत्र।
				11 के0 व्ही 0 टी0व्ही फीडर	राजस्व कालोनी, डिग्रेजी नगर, मुक्तिधाम चौक, गुरुबिहार, पादक गौरी एवं आसपास का क्षेत्र।

" विद्युत संबंधित शिकायतें केंद्रीय कॉन्ट्रोल सेंटर के फोन नं0 1912 पर करे करार है। "

" विद्युत देयक का भुगतान नियमित करें। " अनुबन्ध के लिए खरे करें। "

कार्यपालन अभियंता (नगर-दो) पश्चिम

छ0रं0पां0डि0क0 लिमि0, बिलासपुर

स.

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना



MATS UNIVERSITY

UGC GRADED AUTONOMY



CHHATTISGARH'S FIRST AND ONLY STATE PRIVATE UNIVERSITY ACCREDITED WITH **A+** GRADE BY NAAC

CHHATTISGARH'S OLDEST PRIVATE UNIVERSITY
ONE UNIVERSITY: THREE MODES, ENDLESS OPPORTUNITIES.
REGULAR | DISTANCE | ONLINE
ADMISSION OPEN 2026-27

MATS School of Engineering & Information Technology

Diploma

Mechanical/ Mining/ Civil/ CSE

B.Tech.

CSE - Artificial Intelligence and Machine Learning/
Data Science/ Block Chain Technology/
Cyber Security and Internet of Things (IOT)
Civil - Smart Cities/ Green Technology and Sustainability
Mining - Mining and Mineral Process, GIS & Remote Sensing
Aeronautical - Unmanned Aerial Vehicle , Space Robotics
Mechanical - Additive Manufacturing, Robotics & Automation

University name for
Online Admission Counseling in
<https://cgdte.admissions.nic.in/>:
**MATS SCHOOL OF ENGINEERING
AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

M.Tech.

CSE/ Turbo Machinery
Power Electronics/ Computer
Aided Structural Engineering

School of Education

Chhattisgarh's First Private University
offering Integrated Teachers
Education Programme

B.Com. B.Ed.(4Yrs.)
B.Sc. B.Ed.(4Yrs.)
B.A. B.Ed.(4Yrs.)

Admission through
NTA - NCET Ranking 2026

Admission Help Line : 9109951182, 9755199381

Admission Help Line : 9109951184

School of Arts & Humanities

Psychology

B.Sc. Applied Psychology
M.Sc./ M.A.
Clinical Psychology/ Counselling Psychology
Industrial Psychology.
Admission Help Line : 7471180268

B.A.

English with Mass Communication
Hindi Journalism with Mass Communication
History/ Political Science/ Sociology/ Economics

Admission Help Line : 7880001773, 9752942949

M.A.

English
Hindi
Political Science
Education

Social Work

B.S.W.
M.S.W.
Specialisation in Psychiatric Social Work
Admission Help Line : 9109994500

School of Design

B.Sc.

Fashion Design/ Interior Design

M.Design

Admission Help Line : 9109951183



EXPLORE OUR WIDE RANGE OF ACADEMIC PROGRAMMES

Management & Business Studies

B.B.A.
B.Com.
M.Com.
M.B.A.
Marketing / Finance/
Human Resource Management
Digital Marketing
Artificial Intelligence
Healthcare & Hospital Management
Production & Operations Management
Admission Help Line :
9109913111, 7389376989

Law

B.A. LL.B.
LL.B.
LL.M. 1yr/2yr
Admission Help Line :
9109997900

Physical Education

M.A. Yoga
B.P.Ed.
Admission Help Line :
9755199381

SCAN FOR
VIRTUAL TOUR OF
MATS UNIVERSITY



Science

B.Sc.
Biotechnology/ Microbiology
Forensic Science/ CBZ/ PCM
M.Sc.
Microbiology/ Chemistry
Biotechnology/ Zoology
Mathematics/ Botany
Forensic Science
Admission Help Line :
7389356989, 9109991032

Library Science

M.Lib.I.Sc.
B.Lib.I.Sc.
Admission Help Line :
91099991031

Information Technology

M.C.A.
Web Technology (Full Stack Development)
Data Science (AI, ML, Data Analytics)
M.Sc.(CS)
Cyber Security/ Cloud Computing
B.C.A.
Web Technology (Full Stack Development)
Data Science (AI, ML, Data Analytics)
B.Sc. Animation & Graphic Designing
Admission Help Line : 9109951181

Pharmacy

B. Pharmacy
D. Pharmacy
Admission Help Line : 9755199381

PG Diploma & Diploma

D.C.A.
Diploma in Computer Applications
D.J.M.C.
Diploma in Journalism & Mass Communication
D.G.L.P.
Diploma in Good Laboratory Practice
P.G.D.C.A.
PG Dip. in Computer Applications
P.G.D.F.S.C.
PG Dip. in Forensic Science & Criminology
P.G.D.G.C.
PG Dip. in Guidance & Counseling
P.G.D.Y.Ed.
PG Dip. in Yoga Education
Admission Help Line: 91099994500